BYJU'S EXAM PREP

Weekly Current Affair

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

(17-23 April 2022)

Weekly Current Affairs

Table of Contents

International Relations .....

National.....

State.....

Economy.....

Defence.....

Science & Technology .....

Environment .....

Sports.....

Awards And Honours.....

Appointment/ Resignation.....

Obituaries .....

Important Days.....

International Relations

1. सऊदी दबाव में यमनी राष्ट्रपति अब्दराबुह हादी ने इस्तीफा दिया

चर्चा में क्यों?

- यमन के राष्ट्रपति अब्दराबुह मंसूर हादी ने सऊदी अरब के दबाव में पद छोड़ दिया और अब वास्तव में नजरबंद हैं।

प्रमुख बिंदु

- अब्दराबुह मंसूर हादी ने देश में 7 साल के युद्ध के बाद पद छोड़ दिया और अपनी शक्तियां नव निर्मित राष्ट्रपति परिषद को सौंप दी, जिसमें 8 राजनीतिक नेता शामिल हैं।
- सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अंतर-यमनी परामर्श के बाद परिषद के गठन की घोषणा की गई, जहां सऊदी नेतृत्व ने यमन में शांति स्थापित करने के लिए हौथियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए परिषद को बुलाया, जो वर्षों से हिंसक संघर्ष से घिरा हुआ था।

यमन के बारे में तथ्य:

- यमन, आधिकारिक तौर पर यमन गणराज्य, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी एशिया में एक देश है।
- **राजधानी:** सना
- **मुद्रा:** येमेनी रियाल

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

2. यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को "आतंकवाद के राज्य प्रायोजक" के रूप में नामित करने का अनुरोध किया

चर्चा में क्यों?

- यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति जो बिडेन से रूस को **"आतंकवाद के राज्य प्रायोजक"** के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उपलब्ध प्रतिबंधों के सबसे कठोर सूट को सक्रिय करेगा।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी विदेश मंत्री (मुख्य रूप से विदेशी संबंधों के प्रभारी मंत्री) के पास "आतंकवाद के राज्य प्रायोजक" के रूप में "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए बार-बार समर्थन प्रदान करने वाले देशों" को नामित करने की शक्ति है।
- अमेरिका इस सूची में शामिल देशों पर **चार तरह के प्रतिबंध** लगा सकता है: अमेरिकी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध; रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध; दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण; और विविध वित्तीय और अन्य प्रतिबंध।
- उन देशों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो निर्दिष्ट देशों के साथ कुछ व्यापार में संलग्न हैं।

सूची में शामिल देश:

- अब तक, आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में चार देश हैं।
- उनमें से सबसे पहले सीरिया (29 दिसंबर, 1979), उसके बाद ईरान (19 जनवरी, 1984) और उत्तर कोरिया (20 नवंबर, 2017) को नामित किया गया था। 12 जनवरी, 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया गया था।

पदनाम अधिकृत करने वाले क़ानून:

- वर्तमान में तीन क़ानून हैं जो राज्य के सचिव को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए बार-बार समर्थन प्रदान करने के लिए एक विदेशी सरकार को नामित करने के लिए अधिकृत करते हैं:

(i) 1961 के विदेशी सहायता अधिनियम की धारा 620A

(ii) आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट (AECA) की धारा 40

(iii) 2018 के निर्यात नियंत्रण अधिनियम की धारा 1754 (C)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

National

3. केंद्र ने 3 नागा समूहों के साथ युद्धविराम समझौते को एक साल के लिए बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने 3 नागा समूहों के साथ युद्धविराम समझौते को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- समूहों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड- NK (NSCN-NK), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-रिफॉर्मेशन (NSCN-R) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-K-खांगो (NSCN-K-खांगो) शामिल हैं।
- ये सभी समूह NSCN-IM और NSCN-K के अलग हुए गुट हैं।
- गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इन युद्धविराम समझौतों को एक वर्ष की एक और अवधि के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। NSCN-NK और NSCN-R के साथ यह युद्धविराम समझौता 28 अप्रैल, 2022 से लेकर 27 अप्रैल, 2023 तक और NSCN-K--खान्गो के साथ यह युद्धविराम समझौता 18 अप्रैल, 2022 से लेकर 17 अप्रैल, 2023 तक प्रभावी रहेगा।

नोट:

- केंद्र ने सितंबर 2021 में NSCN-K के निकी सूमी गुट के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- केंद्र ने अगस्त 2015 में NSCN (IM) के साथ एक "फ्रेमवर्क एग्रीमेंट" पर हस्ताक्षर किए थे।

अन्य संबंधित शांति समझौते:

- बोडो शांति समझौता, 2020
- ब्रू अकॉर्ड, 2020
- कार्बी आंगलोंग समझौता, 2021

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

4. NITI आयोग ने बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा जारी किया

चर्चा में क्यों?

- NITI आयोग ने हितधारकों के सुझावों के लिए **बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा** जारी किया।

प्रमुख बिंदु

बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा के बारे में:

- इस नीति के तहत, पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- बढ़ते शहरों में दोपहिया और तिपहिया वाहन खंडों के महत्व को देखते हुए सभी प्रमुख शहरों जैसे राज्य की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दूसरे चरण के तहत कवर किया जाएगा।
- स्वैपेबल बैटरी वाले वाहन बिना बैटरी के बेचे जाएंगे, जिससे संभावित EV मालिकों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा।

नोट:

- ग्लासगो में COP-26 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने कार्बन उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करने, 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक ले जाने, 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा करने और अंत में 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
- कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन का प्रमुख हिस्सा सड़क परिवहन क्षेत्र से आता है, जिसमें सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन का एक-तिहाई शामिल होता है।
- कई सहायक पहलों को लागू किया गया है, जैसे भारत में बिजली-चालित (हाइब्रिड) वाहनों को तेजी से अपनाना और इनका विनिर्माण (FAME) I और II, राष्ट्रीय उन्नत सेल (ACC) बैटरी भण्डारण कार्यक्रम (NPACC) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, स्वदेशी बैटरी निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना आदि।

स्रोत: ET

5. भारत हिमाचल में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा

चर्चा में क्यों?

- भारत जल्द ही लद्दाख में ज़ांस्कर घाटी और हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के बीच 16,580 फीट ऊंचे शिंकू-ला दर्रे के नीचे दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सुरंग 2025 तक तैयार हो जाएगी, और लद्दाख और हिमाचल के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने बताया कि **शिंकू-ला सुरंग** की लंबाई 4.25 किमी होगी।

नोट:

- **अटल टनल**, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह-मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है।
- 9.02 किमी की लंबाई में, यह दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे सिंगल-ट्यूब टनल है।

स्रोत: TOI

6. गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया

चर्चा में क्यों?

- गुजरात के गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में **भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम** का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मंदिर परिसर में 10 PV पोर्ट सिस्टम की स्थापना को जर्मन विकास एजेंसी ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (GIZ) द्वारा समर्थित किया गया है।
- पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम स्थापित किए गए हैं।
- PV पोर्ट्स का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड (SPSL) द्वारा किया गया है, जो मेक इन इंडिया परियोजना के तहत सौर उत्पादों की अग्रणी निर्माता है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

7. ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया

चर्चा में क्यों?

- ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने असम में "भारत का पहला 99.999% शुद्ध" ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है।

प्रमुख बिंदु

- ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रति दिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की। इसके साथ ही भारत ने **ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था** की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है।
- संयंत्र मौजूदा 500 किलोवॉट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवॉट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (AEM) इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है।
- इस संयंत्र से भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है।

स्रोत: द हिंदू

8. प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अप्रैल, 2022 को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में **वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन** का उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ टेड्रोस घेब्रेयसस उपस्थित थे।

प्रमुख बिंदु

- यह शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को उजागर करने में मदद करेगा, और नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और वेलनेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा।
- प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर डिजिटल रूप से आयुष निर्यात संवर्धन परिषद का भी शुभारंभ किया।
- उन्होंने आयुष सूचना हब, आयुष नेक्स्ट, आयुसॉफ्ट आदि जैसी IT पहल भी शुरू कीं।

- उन्होंने भारतीय वीज़ा- आयुष वीज़ा के लिए एक नई श्रेणी बनाने की भी घोषणा की, ताकि विदेशी आयुष क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता का लाभ उठा सकें।
- भारत एक विशेष आयुष मार्क भी बनाने जा रहा है। भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादों पर ये मार्क लगाया जाएगा।
- FSSAI ने पिछले सप्ताह अपने नियमों में 'आयुष आहार' नाम की एक नई श्रेणी की भी घोषणा की है।

नोट:

- 2014 में आयुष सेक्टर 3 अरब डॉलर से भी कम था, जो अब 18 अरब डॉलर को पार कर गया है।
- रक्षा मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इनमें पहला MoU 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए है। वहीं, दूसरा समझौता ज्ञापन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के संबंध में है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

9. केंद्र सरकार ने निधि नियम, 2014 में संशोधन किया

चर्चा में क्यों?

- **कंपनी कार्य मंत्रालय** ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आम जनता के हितों की रक्षा के लिए **निधि नियम, 2014** में संशोधन किया।

सत्यमेव जयते

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

प्रमुख बिंदु

- कम्पनी कानून, 1956 के तहत, एक निधि या म्यूचुअल बेनेफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कम्पनी है जिसे केन्द्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के रूप में घोषित किया है।
- कम्पनी कानून, 2013 के तहत, शुरू में किसी कम्पनी को निधि कम्पनी के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार से घोषणा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- ऐसी कम्पनियों को केवल निधि के रूप में शामिल करना आवश्यक होता था और निधि नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत आवश्यकताएं पूरी करनी होती थीं, जैसे कि 200 की न्यूनतम सदस्यता, 10 लाख रुपये की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि, NOF को 1:20 के अनुपात में जमा करना होता था और निधि नियम, 2014 के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर 10 प्रतिशत भार मुक्त जमा राशि नियत वाणिज्यिक बैंकों या डाकघरों में जमा करनी होती थी।

- कम्पनी कानून, 2013 में 15.08.2019 के संशोधन और निधि नियमों, 2014 में परिणामस्वरूप 15.08.2019 से हुए संशोधन के बाद निधियों के रूप में शामिल की गई कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे शामिल होने के 14 महीनों के भीतर घोषणा के लिए फॉर्म NDH-4 में केन्द्र सरकार को आवेदन करें, यदि उन्हें निधि (संशोधन) नियमों के 15.08.2019 से प्रभावी होने के बाद और निधि (संशोधन) नियमों के लागू होने के 09 महीने के भीतर, 2014 के बाद लेकिन 15.08.2019 से पहले निधि के रूप में शामिल किया जाता है।

नोट:

- कम्पनी कानून, 1956 के तहत लगभग 390 कम्पनियों को केवल निधि कम्पनी घोषित किया गया था।
- 2014-2019 के दौरान, दस हजार से अधिक कम्पनियों को शामिल किया गया।

स्रोत: PIB

10. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967

चर्चा में क्यों?

- आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और सहयोगी सदस्य शेख सज्जाद को **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967** के तहत एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, शेख सज्जाद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सक्रिय रूप से कट्टरपंथी, प्रेरित और भर्ती कर रहा है और आतंकी फंडिंग में शामिल रहा है।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के बारे में:

- यह भारत में गैरकानूनी गतिविधियों के संघों की रोकथाम के उद्देश्य से एक भारतीय कानून है।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना था।

- कानून के सबसे हालिया संशोधन, **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 (UAPA 2019)** ने केंद्र सरकार के लिए कानून की उचित प्रक्रिया के बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना संभव बना दिया है।
- UAPA को आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

11. प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अप्रैल 2022 को गुजरात के जामनगर में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ टेड्रोस घेब्रेयसस की उपस्थिति में **WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM)** की आधारशिला रखी।
- प्रधानमंत्री ने बनासकांठा जिले के दियोदर में एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। नया डेयरी कॉम्प्लेक्स एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है।

प्रमुख बिंदु

WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM) के बारे में:

- GCTM दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपुट केंद्र होगा।
- यह वैश्विक कल्याण के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा।
- यह डेटा, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा और पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग का अनुकूलन करेगा।

नोट: 2016 में, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ एक PCA (परियोजना सहयोग समझौता) पर हस्ताक्षर किए थे।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

12. क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत के दौरे पर फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री मीका लिंटिला ने केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने **क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर** स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए तीन प्रमुख संस्थानों जैसे IIT मद्रास, IISER पुणे और C-DAC पुणे की पहचान की है।
- भारत फिनलैंड R&D संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग विकसित करने और फिनिश उद्योग के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग विकसित करने का इच्छुक है, विशेष रूप से निम्नलिखित प्रौद्योगिकी डोमेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्रों जैसे सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जैव आधारित अर्थव्यवस्था, बायोबैंक और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जैव आधारित सामग्री, जल और समुद्री प्रौद्योगिकी, खाद्य और कृषि प्रौद्योगिकियां, वहनीय स्वास्थ्य देखभाल, उन्नत विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियां, AI और मशीन का एकीकरण सभी डोमेन में सीखना आदि क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर रहा है।

नोट: भारत और फिनलैंड दोनों अंटार्कटिक संधि के सलाहकार सदस्य हैं और अंटार्कटिका में उनके सक्रिय स्टेशन हैं। फिनलैंड 2023 में और 2024 में भारत **अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक (ATCM)** की मेजबानी करेगा।

स्रोत: द हिंदू

13. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX इंडिया)

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकारी अधिकारियों और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के लिए **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX इंडिया)** का आयोजन किया।

- राष्ट्रीय साइबर अभ्यास (NCX) इंडिया का आयोजन दस दिनों की अवधि यानि 18 से 29 अप्रैल 2022 तक एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX इंडिया) के बारे:

- कार्यक्रम का संचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), भारत सरकार द्वारा ज्ञान भागीदार के रूप में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) के सहयोग से तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के समर्थन से किया जा रहा है।
- प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म साइबरएक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जो एस्तोनिया की साइबर सुरक्षा कंपनी है और इसे विश्व स्तर पर कई बड़े साइबर अभ्यास आयोजित करने की मान्यता मिली हुई है।
- प्रतिभागियों को प्रमुख साइबर सुरक्षा क्षेत्रों जैसे घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, वायरस (मैलवेयर) सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म (MISP), जोखिम प्रबंधन और प्रवेश परीक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल और डेटा प्रवाह, डिजिटल फोरेंसिक, आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

साइबर सुरक्षा पहल:

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
- साइबर सुरक्षित भारत पहल
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

स्रोत: PIB

14. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

चर्चा में क्यों?

- **'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP), COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना'** की अवधि 19 अप्रैल, 2022 से 180 दिन और बढ़ा दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस बीमा पॉलिसी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना जारी रखा जा सके जो COVID-19 रोगियों की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के बारे में:

- PMGKP को 30 मार्च, 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो COVID-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं और सीधे संपर्क में रहे हैं तथा जिन्हें COVID-19 से प्रभावित होने का खतरा हो सकता है।
- इसके अलावा अप्रत्याशित स्थिति के कारण राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, AIIMS और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/अस्पतालों COVID-19 रोगियों की देखभाल के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा विशेष रूप से तैयार अस्पतालों द्वारा अधिग्रहण किए गए निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक वेतन/एडोक/आउटसोर्स स्टाफ भी PMGKP के अंतर्गत आते हैं।
- योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक उन 1905 स्वास्थ्य कर्मियों के दावों का निपटारा किया जा चुका है, जिनकी COVID संबंधित कार्यों के लिए तैनात किए जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी।

नोट: इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)** को और 6 महीने के लिए सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया था।

स्रोत: PIB

15. भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति

चर्चा में क्यों?

- 2020 में, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की अवधारणा की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- भारत के नेटवर्क पर साइबर हमलों में वृद्धि के बीच, केंद्र ने अभी तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को लागू नहीं किया है, जो 2020 से काम कर रही है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता:

- साइबर हमलों की बढ़ती संख्या: अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक लक्षित राज्य था - सभी रैंसमवेयर हमलों का 42% सामना करना पड़ रहा था।
- साइबर युद्ध के अपराध
- COVID के बाद डिजिटल उपयोग में वृद्धि
- इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) द्वारा रिपोर्ट की गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, 2020 के पहले आठ महीनों में 6.97 लाख साइबर सुरक्षा घटनाएं हुईं, जो पिछले चार वर्षों के संयुक्त रूप से लगभग बराबर हैं।

साइबर सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार की पहल:

- साइबर स्वच्छता केंद्र
- साइबर सुरक्षित भारत पहल
- ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

स्रोत: द हिंदू

16. भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-2019 में 12.3% घटी: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

- विश्व बैंक के एक नीति शोध कार्य पत्र के अनुसार, भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% कम है। गरीबी की संख्या 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी।
- 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7% की गिरावट आई जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई।
- अध्ययन के अनुसार, छोटे आकार के जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया है। 2013 और 2019 में दो सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2% की वृद्धि हुई है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

17. मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत के 8 दिवसीय दौरे पर पहुंचे

चर्चा में क्यों?

- **मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ** दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक दोनों क्षेत्रों, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा में संबंधों को मजबूत करने के लिए आठ दिवसीय यात्रा (17 से 24 अप्रैल, 2022) पर भारत में हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत और मॉरीशस के बीच विशिष्ट रूप से घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, संस्कृति और विरासत से बंधे हैं।
- जगन्नाथ 19 अप्रैल को जामनगर में WHO-ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास समारोह और 20 अप्रैल को गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिरकत करेंगे।
- भारत 2007 से मॉरीशस को माल और सेवाओं का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निर्यातक रहा है।
- मॉरीशस को भारत का निर्यात बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पादों का है। पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा, मॉरीशस को भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुएं फार्मास्यूटिकल्स, अनाज, कपास, आदि हैं। भारत को मॉरीशस के निर्यात की मुख्य वस्तुएं वैनिला, चिकित्सा/सर्जिकल विज्ञान के लिए उपकरण, सुई, एल्यूमीनियम मिश्र धातुएं हैं।

नोट:

- मार्च 2022 में, मॉरीशस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, भारत, श्रीलंका और मालदीव के एक समूह का सदस्य बन गया। इन देशों के NSA का समूह समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए काम करता है।
- इससे पहले जनवरी 2022 में, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरीशस में भारत-सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया था। उन्होंने मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर PV फार्म परियोजना का भी शुभारंभ किया जो भारत के विकास समर्थन के तहत किया जा रहा है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

18. कृषि मंत्री ने पौध संरक्षण प्रभाग के दो ऑनलाइन पोर्टल CROP और PQMS लॉन्च किए

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दो पोर्टलों की शुरुआत की, पहला पोर्टल **कीटनाशक के कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण (CROP)** के लिए और दूसरा पोर्टल **पादप संगरोध सूचना प्रणाली (PQIS)** के लिए है।

प्रमुख बिंदु

- नए पोर्टल से किसानों और निर्यातकों के साथ-साथ उद्योगपतियों को भी फायदा होगा।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि और किसान कल्याण विभाग (DAFW), पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (DPPQS), फरीदाबाद के माध्यम से भारतीय निर्यातकों और कृषि वस्तुओं तथा भारतीय कीटनाशक उद्योग के आयातकों की जरूरतों को अपने दो पोर्टल, कीटनाशक का कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण (CROP) और पादप संगरोध सूचना प्रणाली (PQIS) के माध्यम से पूरा कर रहा है।
- PQMS पोर्टल आवेदकों के लिए बिना किसी भौतिक स्पर्श बिंदु के एक पारदर्शी प्रणाली प्रदान करेगा और ऑनलाइन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सुविधा सुनिश्चित करेगा, जिसमें ई-भुगतान और दस्तावेजों को अपलोड करना, ऑनलाइन मान्यता और उपचार एजेंसियों / सुविधाओं का नवीनीकरण तथा प्रमाण पत्र डाउनलोड करना शामिल है।
- इसी तरह, पुन: विकसित CROP पोर्टल व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा तथा देश के किसानों को अधिक और समय पर फसल सुरक्षा समाधान प्रदान करेगा।

स्रोत: न्यूजऑनएयर

19. 40वां 'हुनर हाट'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में **'हुनर हाट' के 40वें संस्करण** का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 'स्वदेशी' उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय मंच 'हुनर हाट' का 40वां संस्करण 16 से 27 अप्रैल, 2022 तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है।
- हुनर हाट के इस 40वें संस्करण में 31 राज्यों से आए एक हजार से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने 400 स्टॉल लगाए हैं।
- मंत्री महोदय ने **'एक जिला एक उत्पाद'** के बारे में भी बताया, जिसके तहत प्रत्येक जिले को एक उत्पाद के लिए मान्यता दी जाती है।
- श्री ठाकुर ने सरकार द्वारा शुरू की गई **तेजस कौशल कार्यक्रम** के बारे में भी जानकारी दी जिसके तहत भारत UAE को कुशल जनशक्ति भेजेगा।
- **USTTAD** (विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन) योजना के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है।

स्रोत: PIB

20. भारत में मानवाधिकार रिपोर्ट 2021: संयुक्त राज्य अमेरिका

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी विदेश विभाग ने 2021 में भारत में मानवाधिकारों पर एक मजबूत और आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट हर साल अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की जाती है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- भारतीय कानून 'मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नज़रबंदी' पर रोक लगाते हैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएँ सामने आईं, जिसमें पुलिस ने 'गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा को स्थगित करने के लिये विशेष सुरक्षा कानूनों' का उपयोग किया।
- भारत में "महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दे" हैं जैसे "हिंसा सहित स्वतंत्र अभिव्यक्ति और मीडिया पर प्रतिबंध" और "हिंसा की धमकी, या पत्रकारों के खिलाफ अनुचित गिरफ्तारी या मुकदमा"।
- रिपोर्ट के भारत अध्याय में सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ "आतंकवादियों और चरमपंथियों की हत्या, हिंसा और डराने-धमकाने" का भी हवाला दिया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट में फ्री से आंशिक रूप से फ्री में डाउनग्रेड किया गया था, और कहा कि सरकार ने पिछले साल किसानों के विरोध को कवर करने वाले कई पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था।

- इस रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से संबंधित विवाद पर भी प्रकाश डाला गया, जिनकी संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ज़ब्त कर ली गई थी और कथित उल्लंघनों के लिये राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (CHRI) के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया था।

भारत में मानवाधिकार संबंधी प्रावधान:

संविधान में प्रतिपादित:

- मौलिक अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक
- राज्य के नीति निदेशक तत्व: संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक

सांविधिक प्रावधान:

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 (2019 में संशोधित)
- भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के प्रारूपण में सक्रिय भाग लिया

स्रोत: द हिंदू

State

21. दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल 'रेडियो अक्ष' महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ

चर्चा में क्यों?

- दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम **'रेडियो अक्ष'** है, महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास अवम अनुसंधान मंडल (सक्षम) की मदद से लॉन्च किया गया है।

- यह अवधारणा दृष्टिहीन लोगों को उनके डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई गई ऑडियोबुक के विकल्प के रूप में बनाई गई थी, जिसकी पहुंच COVID-19 महामारी के कारण यात्रा पर प्रतिबंध के कारण दूर हो गई थी।

स्रोत: TOI

22. 'e-DAR' (ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, **सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)** ने **'e-DAR' (ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट)** नामक एक पोर्टल विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु

- बीमा कंपनियों के परामर्श से सरकार द्वारा डिज़ाइन किया गया वेब पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा, जिससे पीड़ितों के परिवारों को राहत मिलेगी।
- आसान पहुंच के लिए डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- वेब पोर्टल को एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) से जोड़ा जाएगा।
- iRAD से, 90% से अधिक डेटासेट के लिए एप्लिकेशन सीधे e-DAR में पंहुचा दिए जाएंगे।
- पुलिस, सड़क प्राधिकरण, अस्पताल आदि जैसे हितधारकों को e-DAR फॉर्म के लिए बहुत कम जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
- e-DAR iRAD का विस्तार और ई-संस्करण होगा।

सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य पहलें:

भारत:

- मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019
- सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007
- राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998

वैश्विक स्तर:

- सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (2015)
- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह
- अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP)

स्रोत: द हिंदू

23. पहली बार, महाराष्ट्र ऐप ने ICDS योजना की पोर्टेबिलिटी के लिए श्रमिकों के प्रवास को मैप किया

चर्चा में क्यों?

- देश में अपनी तरह की पहली परियोजना में, महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से कमजोर मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए एक वेबसाइट-आधारित **माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (MTS)** एप्लिकेशन विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग ने पिछले साल नवंबर में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अमरावती, जालना, पालघर और नंदुरबार सहित उच्च आदिवासी आबादी वाले छह जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था।
- MTS परियोजना की परिकल्पना आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 18 वर्ष तक के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं सहित प्रवासी लाभार्थियों को पोषण आपूर्ति, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच आदि जैसी **समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS)** की निरंतरता को बनाए रखने के लिए की गई है।
- राज्य के भीतर या बाहर अपने गंतव्य जिलों में अपने मूल स्थानों पर लौटने तक उनके परिवारों के लिए ICDS की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रवास को ट्रैक किया जाएगा।

समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के बारे में:

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसे 1975 में शुरू किया गया था।

ICDS के तहत योजनाएं:

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- आंगनवाड़ी सेवा योजना
- राष्ट्रीय शिशु गृह योजना

- किशोरियों के लिए योजना
- पोषण अभियान
- बाल संरक्षण योजना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Economy

24. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 'फिन्क्लुवेशन' लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

- **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)** ने **'फिन्क्लुवेशन'** - वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह-सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल- लॉन्च करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

फिन्क्लुवेशन के बारे में:

- फिनक्लुवेशन सहभागी स्टार्टअप्स के साथ समावेशी वित्तीय समाधानों को सह-सृजित करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का एक स्थायी प्लेटफॉर्म होगा।
- फिन्क्लुवेशन स्टार्टअप्स को सहभागी बनने, विचार देने, सहज तथा अनुकूल उत्पादों एवं सेवाओं- जिन्हें ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है, का विकास तथा विपणन करने के लिए आमंत्रित करता है।
- फिन्क्लुवेशन स्टार्टअप्स को IPPB तथा डाक विभाग विशेषज्ञों के साथ समाधान विकसित करने के लिए तथा डाक नेटवर्क और IPPB की प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग करते हुए प्रायोगिक परियोजना का संचालन करने के लिए काम करने की अनुमति देगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के बारे में:

- IPPB की स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत, भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ की गई है।
- इसे 1 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।

स्रोत: PIB

25. IMF ने भारत की FY23 GDP वृद्धि का अनुमान पहले के 9% से घटाकर 8.2% कर दिया

चर्चा में क्यों?

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने हाल ही में जारी अपनी नवीनतम **विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट** में, भारत के वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- IMF ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक विकास दृष्टिकोण को भी 4.4 प्रतिशत से घटाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया है, यह कहते हुए कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता और यूरोप में युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण काफी खराब हो गई हैं।

नोट: इससे पहले, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में 8 प्रतिशत की कटौती की है। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत के विकास अनुमान में 7.2 प्रतिशत की तेजी से कटौती की है, जबकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान में कहा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.9 प्रतिशत होगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में तथ्य:

- **स्थापना:** 27 दिसंबर 1945
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन, DC, US
- **सदस्यता:** 190 देश
- **प्रबंध निदेशक:** क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
- **प्रथम उप प्रबंध निदेशक:** गीता गोपीनाथ

स्रोत: TOI

26. LIC में 20% FDI की अनुमति देने के लिए सरकार ने FEMA नियमों में संशोधन किया

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)** के नियमों में संशोधन किया है, जिससे बीमा दिग्गज **LIC** में 20 प्रतिशत तक **FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)** का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- सरकार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए LIC में अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रही है।
- LIC ने फरवरी, 2022 में IPO के लिए बाजार नियामक SEBI के समक्ष ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया था।
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद, 14 मार्च, 2022 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने मेगा पब्लिक ऑफर से पहले LIC में विदेशी निवेश की सुविधा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया था।
- FDI नीति में बदलाव सहित एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी DPIIT के प्रावधानों को लागू करने के लिए FEMA अधिसूचना की आवश्यकता थी, जो बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को LIC के शेयरों की सदस्यता लेने की अनुमति देगा।
- इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है।
- अधिसूचना में मौजूदा नीति में एक अनुच्छेद डाला गया है, जिसमें LIC में स्वचालित मार्ग से 20 प्रतिशत तक FDI की अनुमति है।
- LIC में विदेशी निवेश समय-समय पर संशोधित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, (LIC अधिनियम) के प्रावधानों और बीमा अधिनियम, 1938 के ऐसे प्रावधानों के अधीन होगा, जो समय-समय पर संशोधित होते हैं, जैसा कि LIC में लागू होते हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के बारे में:

- FEMA भारत की संसद का एक अधिनियम है "बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए"।
- इसे 1999 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) की जगह संसद में पारित किया गया था।
- इसने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के उभरते ढांचे के अनुरूप एक नई विदेशी मुद्रा प्रबंधन व्यवस्था को सक्षम किया।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

Defence

27. मुंबई में छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'INS वागशीर' को समुद्र में उतारा गया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना में यार्ड 11880, प्रोजेक्ट- 75 के तहत कलवरी श्रेणी से आने वाली पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी **'INS वागशीर'** का मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL) के कन्होजी आंग्रे वेट बेसिन में जलावतरण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रोजेक्ट- 75 के अंतर्गत निर्मित पनडुब्बियों की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 2017 में नौसेना में कमीशन किया गया था और वर्तमान में इस परियोजना की चार पनडुब्बियां (INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज, और INS वेला) भारतीय नौसेना की सेवा में कार्यरत हैं।
- पांचवीं पनडुब्बी 'INS वागीर' समुद्री परीक्षण के साथ आगे बढ़ रही है और इस वर्ष इसकी डिलीवरी होने की संभावना है।
- श्रृंखला की छठी पनडुब्बी अब विभिन्न उपकरणों और उसके बंदरगाह परीक्षणों के लिए तैयार है।
- पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में नवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है।

स्रोत: HT

28. रक्षा सचिव ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 'NATPOLREX-VIII' का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

- रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने गोवा के मोरमुगाओ पत्तन पर भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा आयोजित दो दिवसीय (अप्रैल 19-20, 2022)

राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास - 'NATPOLREX-VIII' के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक और श्रीलंका और बांग्लादेश के दो तटरक्षक जहाज शामिल थे।
- NATPOLREX-VIII का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य SACEP समझौता ज्ञापन के अधीन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (NOSDCP)** में निहित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को लागू करना है, जिसमें भारत एक सदस्य राष्ट्र है।
- आज, भारतीय तटरक्षक बल इस क्षेत्र में उच्चतम स्तर के तेल रिसाव को संभालने में सक्षम है, जो कि 700 टन और उससे अधिक है।

नोट: NATPOLREX के अलावा ICG 18-29 अप्रैल, 2022 तक चेन्नई में हिंद महासागर परिधि संघ (IORA) के सदस्य राष्ट्रों सहित 18 देशों के 45 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए समुद्री तेल प्रतिक्रिया और तैयारी में एक क्षमता निर्माण पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

स्रोत : इंडिया टुडे

Science & Technology

29. भारतीय वैज्ञानिकों ने COVID-19 के लिए प्लाज्मा-आधारित परिशोधक विकसित किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय वैज्ञानिकों ने **शीत वायुमंडलीय दबाव प्लाज्मा (CAP)** की मदद से उत्पन्न प्लाज्मा-आधारित एक कीटाणुनाशक विकसित किया है जो COVID-19 के लिए एक हरे रंग के परिशोधक के रूप में कार्य कर सकता है।

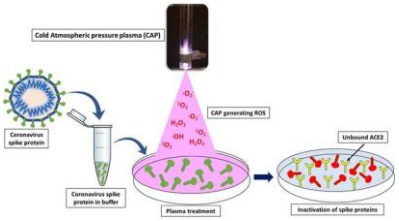

प्रमुख बिंदु

- असम के गुवाहाटी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (IASST), भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान, के जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान प्रभागों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रदर्शित किया है कि शीत वायुमंडलीय दबाव द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा में SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने की क्षमता है, जो वायरल संक्रमण और बाद में COVID-19 को प्रेरित करने के लिए मानव ACE-2 रिसेप्टर यानी अभिग्राहक को जमा देता है अर्थात उसे जकड़ लेता है।
- **प्लाज्मा,** पदार्थ की चौथी अवस्था है जो प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादित होने पर ब्रह्मांड का अधिकांश भाग बनाती है और इसे **शीत वायुमंडलीय दबाव प्लाज्मा (CAP)** कहा जाता है।
- RSC (रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री) एडवांस के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में हाल ही में प्रकाशित इस शोध से पता चलता है कि प्लाज्मा में उत्पन्न अल्पकालिक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रजातियां (ROS/RNS) ने CAP उपचार के 2 मिनट के भीतर SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है।
- RT-PCR विश्लेषण ने यह भी स्थापित किया है कि CAP SARS-CoV-2 वायरस के RNA को निष्क्रिय कर सकता है।

स्रोत: बिजनेस टुडे

Environment

30. वैज्ञानिकों ने केरल, बंगाल से ईल की नई प्रजातियों की खोज की

चर्चा में क्यों?

- भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने केरल और पश्चिम बंगाल में क्रमशः कलामुक्कू और दीघा मोहना मछली पकड़ने के बंदरगाहों से एकत्र किए गए नमूनों में से **ईल की एक नई प्रजाति** की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- नई खोजी गई ईल कांग्रिड ईल समूह से संबंधित है और इसे एरियोसोमा इंडिकम नाम दिया गया है।

- इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (ICAR-NBFGR), लखनऊ और एस्टुरीन बायोलॉजी रीजनल सेंटर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गोपालपुर-ऑन-सी, ओडिशा के वैज्ञानिकों ने एरियोसोमा इंडिकम को एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की है।
- नई प्रजाति की कुल लंबाई 362 मिलीमीटर है।
- एरियोसोमा जीनस में 7 प्रजातियां हैं, जिनमें नई पहचान की गई ईल भी शामिल है, जिन्हें भारतीय जल में प्रलेखित किया गया है। विश्व स्तर पर, जीनस में 223 प्रजातियां हैं।

नोट: नई ईल प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट द्वारा 'खतरे' या 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

स्रोत: DTE

Sports

31. भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा

चर्चा में क्यों?

- भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा।

प्रमुख बिंदु

- स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में अगले साल भारत में 16 देशों की 22 टीमें हिस्सा लेंगी।
- यह इवेंट ICC वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में होगा।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

Awards & Honours

32. प्रधानमंत्री मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए

चर्चा में क्यों?

- **सिविल सेवा दिवस** के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में **लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार** प्रदान किए।

प्रमुख बिंदु

- आम नागरिक के कल्याण के लिए जिलों/कार्यान्वयन इकाइयों और केंद्र/ राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने के लिए लोक प्रशासन में **उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार** स्थापित किए गए हैं।
- उन्हें पहचान किए गए प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी सम्मानित किया जाता है।
- **सिविल सेवा दिवस 2022** पर निम्नलिखित पांच प्राथमिकता कार्यक्रमों के तहत असाधारण कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है: (i) **पोषण अभियान** में "जन भागीदारी" या लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, (ii) **खेलो इंडिया योजना** के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, (iii) **PM स्वनिधि योजना** में डिजिटल भुगतान और सुशासन, (iv) **एक जिला एक उत्पाद योजना** के माध्यम से समग्र विकास, (v) मानवीय हस्तक्षेप के बिना निर्बाध रूप से सेवाओं तक संपूर्ण पहुंच।
- इस वर्ष 5 चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमों और लोक प्रशासन/सेवा वितरण आदि के क्षेत्र में नवाचार के लिए 16 पुरस्कार दिए जाएंगे।

नोट: केंद्र सरकार 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है।

स्रोत: HT

33. डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र का सबसे विशिष्ट पर्यावरण पुरस्कार मिला

चर्चा में क्यों?

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** ने **डेविड एटनबरो** को प्रकृति के संरक्षण और इसकी बहाली के लिए अनुसंधान, प्रलेखन और वकालत के प्रति समर्पण के लिए **चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड** से सम्मानित किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड वैश्विक पर्यावरण समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष में दिया जाता है। स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद से 2022 में पचास साल पूरे हो गए हैं, जो पर्यावरण पर पहली अंतरराष्ट्रीय बैठकों में से एक था।
- सम्मेलन ने दुनिया भर में पर्यावरण मंत्रालयों और एजेंसियों के गठन को प्रेरित किया, सामूहिक रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए कई नए वैश्विक समझौतों की शुरुआत की, और **UNEP** के गठन का नेतृत्व किया, जो इस वर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के बारे में तथ्य:

- **मुख्यालय:** नैरोबी, केन्या
- **स्थापना:** 5 जून 1972
- **कार्यकारी निदेशक:** इंगर एंडरसन

स्रोत: DTE

34. नागरिक विमानन मंत्रालय की "उड़ान" योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया

चर्चा में क्यों?

- नागरिक विमानन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना **उड़ान (UDAN) (उड़े देश का आम नागरिक)** को "नवाचार (सामान्य) - केंद्रीय" श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कार के बारे में:

- भारत सरकार ने राज्य/सरकार के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार का शुभारंभ किया है।
- इस योजना में मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के अलावा सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम मील तक संपर्क पर जोर दिया गया है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पट्टिका और 10 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल है।

नोट: नागरिक विमानन मंत्रालय 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा।

उड़ान योजना के बारे में:

- 2016 में प्रारंभ की गई उड़ान योजना का उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक की अवधारणा का पालन करते हुए टियर II और III शहरों में एक उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई संपर्क के साथ आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
- 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में आज 415 उड़ान मार्ग 66 अंडरसर्व्ड/अनसर्व्ड हवाई अड्डों को जोड़ते हैं, जिसमें हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं और 92 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।
- इस योजना के तहत 1 लाख 79 हजार से अधिक उड़ानें संचालित की गई हैं।
- नागरिक विमानन मंत्रालय वर्ष 2026 तक उड़ान RCS योजना के तहत 1,000 नए मार्गों के साथ भारत में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है और इसके लिए प्रतिबद्ध भी है।

स्रोत: PIB

Appointments/Resignations

35. सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने 30 अप्रैल, 2022 से लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे, जो वर्तमान में थल सेना उप प्रमुख हैं, को अगला थल सेना प्रमुख (29वें) नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- मनोज सी पांडे थल सेनाध्यक्ष बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं।
- वह जनरल मनोज मुकुंद नरवने का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल को अपना 28 महीने का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं।
- लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को उनकी शानदार सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है।

स्रोत: HT

36. भारत चार UN ECOSOC निकायों के लिए निर्वाचित हुआ

चर्चा में क्यों?

- भारत को **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)** के चार प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है, जिसमें विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- भारत चार संयुक्त राष्ट्र ECOSOC निकायों के लिए निर्वाचित हुआ: सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और राजदूत प्रीति सरन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (CESCR) के लिए फिर से चुनी गईं।

नोट: इससे पहले अप्रैल 2021 में भी, भारत तीन संयुक्त राष्ट्र ECOSOC निकायों के लिए चुना गया था, जिसमें अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, संयुक्त राष्ट्र महिला का कार्यकारी बोर्ड और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड शामिल हैं।

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के बारे में:

- ECOSOC 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं।

स्रोत: इंडिया टुडे

Obituaries

37. महान उड़िया संगीतकार और गायक प्रफुल्ल कर का निधन

- महान उड़िया संगीतकार, गायक, लेखक और गीतकार प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वह 'कमला देश राजकुमार' सहित अपने कई गीतों के लिए लोकप्रिय थे।
- उन्हें 2015 में प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार मिला था और 2004 में जयदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें लगातार छह बार राज्य फिल्म पुरस्कार मिला था।

स्रोत: TOI

38. 18 वर्षीय तमिलनाडु टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व दीनदयालन का निधन

- 18 वर्षीय तमिलनाडु टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व दीनदयालन, जो 83वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए शिलांग जा रहे थे, का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।
- उन्होंने देश और विदेश में कई जूनियर, सब-जूनियर और कैडेट खिताब जीते थे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

39. पाकिस्तानी मानवतावादी कार्यकर्ता बिल्किस बानो एधी का निधन

- पाकिस्तानी मानवतावादी कार्यकर्ता **बिल्किस बानो एधी** का निधन हो गया।
- बिल्किस बानो एधी एक पाकिस्तानी पेशेवर नर्स थीं और देश में सबसे सक्रिय परोपकारी लोगों में से एक थीं।
- बिल्किस ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब्दुल सत्तार एधी फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक कल्याणकारी संगठन है, जिसने कई क्षेत्रों में अपने मानवीय कार्यों के लिए दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की।
- उनके योगदान के लिए, उन्हें लोक सेवा के लिए 1986 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया।

स्रोत: बिजनेस टुडे

Important Days

40. 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस (पृथ्वी दिवस) हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 का **विषय** "हमारे ग्रह में निवेश करें" है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 22 अप्रैल को 2009 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया।
- स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 ने वैश्विक जागरूकता की शुरुआत के साथ-साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना की।

स्रोत: un.org

41. 21 अप्रैल, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय **सिविल सेवा दिवस** हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और लोक प्रशासन में उनके योगदान और कड़ी मेहनत के लिए भारत के सिविल सेवकों को समर्पित है।

प्रमुख बिंदु

- सिविल सेवा दिवस 2022 का **विषय** "विजन इंडिया@2047 - नागरिकों और सरकार को करीब लाना" है।
- पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था।

- भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में चुना क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था।
- ऐतिहासिक अवसर दिल्ली के मेटकाफ हाउस में हुआ था।
- सरदार पटेल ने सिविल सेवकों को 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' कहा था।

42. 18 अप्रैल, विश्व धरोहर (विरासत) दिवस

चर्चा में क्यों?

- स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDMS), जिसे विश्व धरोहर (विरासत) दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व धरोहर दिवस 2022 का **विषय** "विरासत और जलवायु" है।
- स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अप्रैल 1982 को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद (ICOMOS) द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1983 में UNESCO की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

भारत के UNESCO विश्व धरोहर स्थल:

- अंकित किए जाने वाले पहले स्थल अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल थे, जिनमें से सभी को विश्व धरोहर समिति के 1983 के सत्र में अंकित किया गया था।
- अंकित की जाने वाली नवीनतम साइट 2021 में धोलावीरा, गुजरात है।
- जुलाई 2021 तक, भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 में विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्थल (5) हैं।
- वर्तमान में, भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। इनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, और 1 मिश्रित है (सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मानदंडों को पूरा करता है), जैसा कि संगठन के चयन मानदंड द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- भारत में दुनिया में छठी सबसे बड़ी संख्या में स्थल हैं।

विश्व के UNESCO विश्व धरोहर स्थल:

- जुलाई 2021 तक, 167 देशों में कुल 1,154 विश्व धरोहर स्थल (897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित संपत्तियां) मौजूद हैं।
- 58 चयनित क्षेत्रों के साथ, इटली सूची में सबसे अधिक स्थलों वाला देश है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

43. 17 अप्रैल, विश्व हीमोफिलिया दिवस

चर्चा में क्यों?

- हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व हीमोफिलिया दिवस 2022 का **विषय** 'सभी के लिए पहुंच: साझेदारी, नीति, प्रगति' है।
- यह हीमोफिलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जागरूकता दिवस है और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया के संस्थापक फ्रैंक श्नाबेल की जयंती भी है।

हीमोफीलिया के बारे में:

- हीमोफीलिया एक विकार है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव होता है। गंभीर हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को बिना किसी कारण के रक्तस्राव हो सकता है।

स्रोत: HT